

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या- 261504 /xxvii(10)/2024-E-74906/2024
देहरादून, दिनांक- 17, दिसम्बर, 2024

ज०/र०/17/11-24

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : 5वें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का दिनांक-01 जुलाई, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्य-228937/XXVII(10)/2024-E-74906/2024, दिनांक-02 अगस्त, 2024 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से छठवें और सातवें केन्द्रीय वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01.01.2024 से पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में मूल वेतन का 443% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

02. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/6(2)/2024-ई.-II(बी) दिनांक-07 नवम्बर, 2024 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5वें वेतनमान के अनुरूप अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं एवं जिनका वेतन अभी छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01.07.2024 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 443 % को बढ़ाकर 455 % प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

03. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाने होंगे।

04. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान पांचवा वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होगा।

05. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

06. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01, जुलाई, 2024 से दिनांक 31, दिसम्बर, 2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद रूप में किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा।

Signed by

Dilip Jawalkar
(दिलीप जावलकर)

Date: 16-12-2024 18:18:34
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या-261506/xxvii(10)/2024-E-74906/2024
देहरादून : दिनांक 17, दिसम्बर, 2024

611/17. XII. 24

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का दिनांक-01 जुलाई, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-228936/XXVII(10)/2024-74906/2024, दिनांक-02 अगस्त, 2024 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक-01.01.2024 से मूल वेतन का 239% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

02. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/6(1)/2024-ई.-II(बी) दिनांक-07 नवम्बर, 2024 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को दिनांक-01 जुलाई, 2024 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 239% को बढ़ाकर 246% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

03. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

04. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

05. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

06. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2024 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद रूप में किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।